- 19th Year
- Issue: 278
- 16.02.2026 (MONDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

एमएसपी पर राहुल गांधी को अमित शाह का करारा जवाब, कहा-झूठ बोलकर जनता को गुमराह न करें

नयी दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 15 गुना अधिक अनाज खरीदा है। गांधीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। मुझे इस पर हंसी आती है।

यह घटना राहुल गांधी द्वारा 2026 के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सरकार की आलोचना का मुज्य बिंदु बनाने के बाद सामने आई है, खासकर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के संदर्भ में। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के साथ धोखा है, जिससे खरीद प्रणाली कमजोर हो सकती है और एमएसपी और बोनस में कमी आ सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार सस्ते अमेरिकी आयात की अनुमति देती है, जिससे घरेलू एमएसपी अप्रभावी हो सकता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कपास, सोया और मक्का के किसान मूल्य संकट से कैसे निपटेंगे। 13 फरवरी, 2026 को गांधी ने संसद में किसान संघों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जहां उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार पर दबाव डालने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

11 फरवरी को अपने बजट भाषण में, उन्होंने सरकार पर भारतीय किसानों के हितों को विदेशी बाजारों में बेचने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि जहां अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, वहीं भारतीय किसानों को उचित कानूनी एमएसपी से वंचित रखा जा रहा है। उनके आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि संसद में कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपने किसानों से कितना अनाज खरीदा है। यूपीए सरकार के 10 साल और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल। हमने किसानों से एमएसपी पर आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज खरीदा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का बजट 26,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपये किया है।

शाह ने राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दुग्ध और कृषि क्षेत्रों की रक्षा की है और किसानों और मछुआरों को उनके कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी की। इससे पहले दिन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर केंद्र पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि इस समझौते के नाम पर देश में भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है।

महाशिवरात्रि पर लिंगराज समेत ओडिशा के शैव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी

भुवनेश्वर १५/०२ (संवाददाता): महाशिवरात्रि पर रविवार को ओडिशा के शैव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी, अधिकारियों ने सुरक्षा और भीड़-मैनेजमेंट के उपाय बढ़ा दिए हैं। लिंगराज मंदिर, कटक में धबलेश्वर मंदिर, ढेंकनाल में कपिलाश मंदिर, भद्रक में अखंडलमणि मंदिर, बालासोर में चंदनेश्वर, संबलपुर में हुमा मंदिर, पुरी में लोकनाथ मंदिर, गजपति में महेंद्रगिरी, बोलनगीर में हरिशंकर मंदिर और कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर समेत बड़े मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इसी तरह, गजपति, रायगढ़ और कंधमाल जिलों और आंध्र प्रदेश के कुछ आस-पास के जिलों से भक्तों ने सुबह-सुबह गजपति में महेंद्रगिरी पहाड़ी का दौरा किया। गजपति के स्क जतिंद्र कुमार पांडा ने कहा कि महाशिवरात्रि को देखते हुए पहाड़ियों पर पुलिस की पांच प्लाटून तैनात की गई हैं।

गवर्नर हरि बाबू कंभमपति, मुज्यमंत्री मोहन चरण माझी और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। महादीप रात 10 बजे उठाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि उन्हें दिन भर और देर शाम तक लाखों भक्तों के आने की उज्मीद है। पुलिस कमिश्नर ने त्योहार से पहले ट्रैफिक और सुरक्षा की तैयारियों का रिव्यू किया। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर परिसर में और उसके आसपास 41 प्लाटून और लगभग 200 अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

इंडिगो कीफ्लाइट में लिपस्टिक से लिखी बम की धमकी, कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप

कोलकाता १५/०२ (संवाददाता): डिज़रूगढ़ से कोलकाता जा रही इंडिगो की एकज़्फ़्लाइट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, ज़्योंकि विमान के शौचालय में लिपस्टिक से बम की धमकी लिखी हुई मिली थी। एक बार फिर सुरक्षा संबंधी चिंता की यह घटना शिलांग जा रही इंडिगो की एक ज़्लाइट के शहर के हवाई अड्डे पर बम की धमकी के बाद रोके जाने के कुछ ही घंटों बाद सामने आई है, हालांकि बाद में यह धमकी झूठी निकली। अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो की ज़्लाइट संज़्या 6श 6894 कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 7.37 बजे सुरक्षित उतरी और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उसे तुरंत एक अलग स्थान पर ले जाया गया।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया। लैंडिंग के बाद की जांच के दौरान, विमान के शौचालय के अंदर लिपस्टिक से लिखा हुआ एक संदेश मिला, जो बम की धमकी का संकेत दे रहा था। बयान में आगे कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इससे पहले, शिलांग जाने वाली इंडिगो की एक ज़्लाइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिलने के बाद करीब चार घंटे तक फंसी रही। अधिकारियों ने बताया कि ज़्लाइट 6श 7304 के विमान में बम रखे जाने का दावा करने वाला एक हस्तलिखित नोट मिलने के बाद उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया। बाद में यह धमकी झूठी निकली। भारतीय विमानन प्राधिकरण (ड्ढ) के प्रवक्ता के अनुसार, निर्धारित प्रस्थान समय से लगभग 15 मिनट पहले, सुबह करीब 9ः15 बजे एक ज़रू सदस्य को विमान के शौचालय में यह नोट मिला। सूचना मिलते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान का गहन निरीक्षण किया।

इस वर्ष का बजट भारत की एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है-मोदी

नयी दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सशस्त्र बलों को मजबूत करे, जैसा कि केंद्रीय बजट 2026 में किए गए बढ़े हुए आवंटन में परिलक्षित होता है। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत की एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तत्परता का संकेत देता है। इस वर्ष का बजट भारत की एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। बजट कोई मजबूरी से उत्पन्न %अभी या कभी नहीं% वाला क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उत्पन्न %हम तैयार हैं वाला क्षण है। देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा, करेगी। रक्षा बजट में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की जिज़्मेदारी है कि वह मौजूदा हालात के

हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए। हमारे एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) का उद्देश्य वस्त्र, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रग सरकार के समय के 'आर्थिक कुप्रबंधन' की आलोचना करते हुए कहा कि उसने भारत को आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं छोड़ा। संप्रग सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था।पीएम मोदी ने कहा कि सुधार सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसे उसने अपने शज़्दों और भावना में प्रदर्शित किया है।

बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री की जगह जाएंगे ओम बिरला

नयी दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): बांग्लादेश में हुए ऐतिहासिक चुनावों के बाद अब सज़ा हस्तांतरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। आगामी 17 फरवरी को ढाका में आयोजित होने वाले नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करेंगे।बांग्लादेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समारोह के लिए विशेष निमंत्रण भेजा था। हालांकि, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण पीएम मोदी का ढाका जाना संभव नहीं हो पा रहा है। 17 फरवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होनी है। ऐसे में भारत ने अपने लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्पीकर ओम बिरला को भेजने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक संबंधों का प्रतीक है।भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, %समारोह में ओम बिरला की

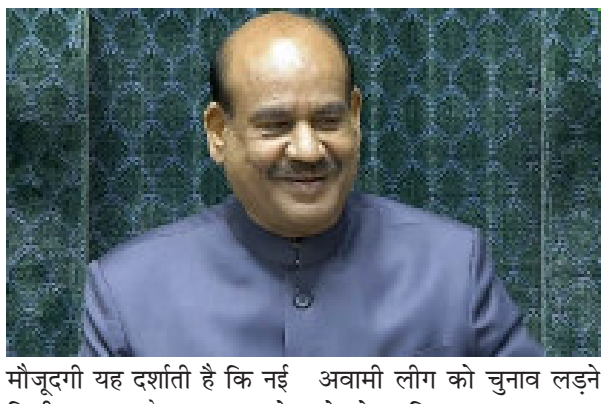

मौजूदगी यह दर्शाती है कि नई दिल्ली, ढाका के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देती है। यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। लगभग दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सज़ा में जोरदार वापसी की है। साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हुए इन पहले राष्ट्रीय चुनावों में बीएनपी ने संसद की 297 सीटों में से 209 सीटों पर जीत दर्ज की है। जमात-ए-इस्लामी 68 सीटें जीतकर दूसरे बड़े दल के रूप में उभरी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इस चुनाव में कुल 59.44ब्त वोटिंग दर्ज की गई। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भी ढाका पहुँचने की उज़्मीद है। मोहज़्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, मलेशिया और श्रीलंका सहित कुल 13 देशों को आमंत्रित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंबे समय बाद स्वदेश लौटे हैं।

ममता ने भाई तारिक रहमान को भेजा जीत का तोहफा, मिठाई-फूलों से दी बधाई

कोलकाता १५/०२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की शानदार जीत के बाद उन्हें फूल और मिठाई भेजी। फूलों और मिठाई का यह उपहार गुलशन स्थित बीएनपी अध्यक्ष के राजनीतिक कार्यालय में पार्टी मीडिया सेल के सदस्य अतीकुर रहमान रुमान ने ग्रहण किया। गुलशन कार्यालय के विशेष अधिकारी मेहेदुल इस्लाम मेहदी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले शुक्रवार को बनर्जी ने एज़्स पर एक पोस्ट में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में मेरे सभी भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। आप सभी को रमजान मुबारक। इस महान विजय

के लिए मेरे तारिक भाई, उनकी पार्टी और सभी पार्टियों को मेरी बधाई। प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। इसी संदेश में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत बने रहने की उज़्मीद जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए रहमान को बधाई दी और कहा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई।13वीं जातीय संसद चुनाव और जनमत संग्रह के लिए मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ। शुक्रवार को बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने 300 में से 297 सीटों के आधिकारिक परिणाम घोषित किए। घोषित 297 सीटों में से बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 212 सीटें हासिल कीं। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के चुनावी गठबंधन ने 77 सीटें जीतीं, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश को एक सीट मिली और निर्दलीय उज़्मीदवारों ने सात सीटें जीतीं।

राजिम कुंभ कल्प छज़ीसगढ़ की अस्मिता एवं पहचान-विष्णुदेव साय

रायपुर १५/०२ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन छज़ीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि छज़ीसगढ़ की अस्मिता और पहचान का प्रतीक पर्व है। मुज़्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजिम में सर्वसुविधायुक्त धर्मशाला निर्माण हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की।

साथ ही, राजिम बैराज कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने और पूर्व में प्रस्तावित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुज़्यमंत्री श्री साय ने मुज़्य मंच पर भगवान राजीव लोचन

की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत भगवान राजीव लोचन, कुलेश्वर महादेव, राजिम दाई, छज़ीसगढ़ महतारी और भारत माता के जयघोष के साथ की। मुज़्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम की पावन भूमि सदियों से तप, त्याग और साधना की साक्षी रही है। छज़ीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाला राजिम अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण विशेष स्थान रखता है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए मुज़्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव त्याग, संयम और सेवा के प्रतीक हैं, जिनका संदेश आज के युग में संतुलन और समर्पण का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवागमन, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

मुज़्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में राजिम कुंभ मेला-स्थल को और अधिक सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाया जाएगा तथा इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक आयोजन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा युवा पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का विराट उत्सव है।

इस वर्ष पंचकोसी धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग की थीम ने आयोजन को विशेष स्वरूप प्रदान किया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प छज़ीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का उत्सव है और इसे राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा एवं साधु-संतों की गरिमामय उपस्थिति थी।

विविध समाचार

कॉरिडोर को उच्च न्यायालयसे हरी झंडी, हिमंता बिस्वा सरमा बोले–जल्द शुरू होगा काम

गुवाहाटी १५/०२ (संवाददाता): असम के मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज़ पोषित कामाज़्या कॉरिडोर परियोजना, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सरमा ने कामाज़्या कॉरिडोर परियोजना में हुई देरी का कारण बताया, जो पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित थी।

असम के मुज़्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज़ पोषित कामाज़्या कॉरिडोर परियोजना पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित थी। उच्च न्यायालय ने आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को इस परियोजना के कामाज़्या के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट दी है कि इस परियोजना का कामाज़्या पारिस्थितिकी तंत्र से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमें कामाज़्या कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 2,200 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू हो चुकी है। डिज़्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 600 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना का प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। हमें जो दो ट्यूबों वाली पानी के नीचे की सुरंग मिल रही है, वह भारत की पहली रेल-सह-सड़क सुरंग है।

शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों में प्रस्तावित मां कामाज़्या मंदिर पहुंच कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका (क्क्षुरु) और एक रिट याचिका का भी निपटारा किया। जनहित याचिका (12/2024) कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। नवज्योति शर्मा द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका [डज़्लूपी(सी) संज़्या 2700/2024] में राज्य द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2023 को जारी एनआईटी के माध्यम से शुरू की गई निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परियोजना से माँ कामाज़्या मंदिर परिसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे अपवित्रता की आशंका है। अदालत ने कहा कि बहस के दौरान, असम के माननीय अधिवक्ता जनरल डी. सैकिया ने इस न्यायालय को मौखिक और लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि संबंधित सभी अधिकारियों से, जिनमें गुवाहाटी स्थित आईआईटी की शोध एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाले जलवैज्ञानिक प्रभावों से संबंधित एक अन्य शोध संस्था की रिपोर्ट शामिल है, सभी मंजूरी प्राप्त होने तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

भारत मंडपम में एआई का सबसे बड़ा इज़्पैज़्ट एज़्सपो, मोदी करेंगे उद्घाटन, 13 देशों की रहेगी नज़र

नयी दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इज़्पैज़्ट समिट के साथ किया जाएगा और इसे कृत्रिम बुद्धिमज़ा के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो नीति, नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन को एक ही मंच पर लाएगा। यह एज़्सपो 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भाग लेंगे।

ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीकी देशों की भागीदारी सहित तेरह देशों के पवेलियन एआई पारिस्थितिकी तंत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करेंगे। 300 से अधिक ज़्यूरेटेड प्रदर्शनी पवेलियन और लाइव प्रदर्शन तीन विषयगत 卐चक्रों卐 – लोग, ग्रह और प्रगति – के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में एआई के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं।

600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप भाग लेने के लिए तैयार हैं, जिनमें से कई वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और व्यापक एआई समाधान विकसित कर रहे हैं जो पहले से ही वास्तविक दुनिया में उपयोग में हैं।

एज़्सपो में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 25 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उज़्मीद है और इसका उद्देश्य एआई पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वैश्विक साझेदारी और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, इस आयोजन के दौरान 3,250 से अधिक वक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इसी बीच, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सज़्मेलन, इज़्पैज़्ट समिट, नई दिल्ली की उस महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करेगाः समावेशी, जिज़्मेदार और प्रभावशाली एआई भविष्य को आकार देना।

इंडियाएआई मिशन के तहत, देश स्वदेशी स्टार्टअप्स और कंसोर्टिया द्वारा विकसित 12 मूलभूत मॉडल पेश कर रहा है, जिन्हें विशाल भारतीय डेटासेट पर प्रशिक्षित किया गया है और देश की 22 आधिकारिक भाषाओं के अनुरूप बनाया गया है।

रायपुर को शहरी बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी पहल

नई दिल्ली/ रायपुर १५/०२ (संवाददाता): राजधानी रायपुर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और शहरी बाढ़ की समस्याओं के निपटारे और बाढ़ के बढ़ते खतरे से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ?220 करोड़ के व्यापक %शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को सैद्धांतिक मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

श्री अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर शहर के लिए इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ?220 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव ह्वष्ठरूको प्रस्तुत किया गया था। 10 नवंबर 2025 को जारी नवीन दिशानिर्देशों के अनुरूप छज़्ीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किए गए, जिसे 23 जनवरी 2026 को राज्य कार्यकारी समिति से विधिवत स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों एवं टिप्पणियों का समाधान करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सहित संशोधित प्रस्ताव पत्र क्रमांक 504/पीडज़्ल्यूडी/एनएनआर/2026 के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद अंतिम स्वीकृति लंबित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि रायपुर के तेजी से होते शहरीकरण के कारण यहाँ का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर (निकासी व्यवस्था) पीछे छूट गया है, जिससे मानसून के दौरान गंभीर जलभराव की स्थिति बन जाती है। भाठागांव, प्रोफेसर कॉलोनी और अवंती विहार जैसे निचले इलाकों के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहाँ भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, 卐जुलाई 2025 में, रायपुर में 33 घंटों के भीतर 103 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई थी और प्रमुख चौराहे ठप हो गए थे। यह फंड शहर के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में कहीं भी जलभराव न हो! यह नया ?220 करोड़ का कार्यक्रम बुनियादी ढांचे की इन कमियों को दूर करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें अस्थायी मरज़्मत के बजाय एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया बाढ़ प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा जो अत्यधिक भारी बारिश को झेलने में सक्षम होगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र को मानसून के दौरान होने वाली जलभराव और बाढ़ की गंभीर समस्या से बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं। यह पहल श्री अग्रवाल की दूरदर्शिता, जनहित के प्रति उनकी संवेदनशीलता और राजधानी रायपुर के सुरक्षित एवं सतत विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से न केवल नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नसीमउद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल

लखनऊ १५/०२ (संवाददाता):उज़र प्रदेश के पूर्व मंत्रिमंडल मंत्री और कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफा देने वाले नेता नसीमउद्दीन सिद्दीकी रविवार को समाजवादी पार्टी में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में शामिल हो गए। उनका यह कदम अगले साल होने वाले उज़र प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच आया है। समाजवादी पार्टी ने कई अन्य प्रमुख नेताओं का भी अपने दल में स्वागत किया, जिनमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व नेता अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, अपना दल (सोनेलाल) के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और दानिश खान शामिल हैं।

सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जहां वे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उनका इस्तीफा राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा के दौरान लखनऊ में हुई एक घटना के बाद आया, जब कथित तौर पर सिद्दीकी को कांग्रेस नेता का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वापस लौटकर इस्तीफा दे दिया।

सिद्दीकी को उज़र प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सिद्दीकी बसपा में फिर से शामिल हो सकते हैं, जिसके साथ उनका कांशी राम के समय से ही लंबा जुड़ाव रहा है। उन्हें मायावती का करीबी माना जाता था, जिन्होंने उज़र प्रदेश की चार बार मुज़्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने चारों कार्यकालों में सिद्दीकी ने कैबिनेट मंत्री पद संभाले। हालांकि, उन्हें 2017 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया था और अगले ही साल वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बीच, एक अन्य महत्वपूर्ण नेता अनीस अहमद खान उर्फ ??फूल बाबू, पीलीभीत से तीन बार विधायक रह चुके हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत केंद्र का बड़ा एज़्शन, 242 सट्टेबाजी और जुए वाली वेबसाइट्स को किया ज़्लॉक

नई दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): केंद्र सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 242 ऑनलाइन बेटिंग और जुए से जुड़ी वेबसाइट्स को ज़्लॉक कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालित किया जा रहा था। सरकार द्वारा पिछले वर्ष लागू किए गए ऑनलाइन गेमिंग एज़्ट के बाद यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

अब तक कुल 7800 से अधिक अवैध बेटिंग और गेज़्बलिंग वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है।सरकार ने बीते साल ऑनलाइन गेमिंग एज़्ट को पारित किया था, जिसका उद्देश्य अवैध सट्टेबाजी और जुए पर प्रभावी रोक लगाना है।

इस कानून के संसद में पेश होते ही ष्ठह्वद्गड्डद्व 11, ख्व 11 ष्टद्बह्यष्द्ग और ख्क्कजैसे कई प्रमुख गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने रियल मनी प्रेडिज़्शन गेज़्स को बंद करने का निर्णय लिया था। एज़्ट लागू होने के बाद यह सरकार की एक और सज़्त कार्रवाई है।

युवाओं और आम लोगों में ऑनलाइन जुए की बढ़ती लत को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक सदन में पेश किया था, जो बाद में कानून का रूप ले चुका है। ऑनलाइन गेमिंग एज़्ट लागू होने से पहले भी सरकार ने वर्ष 2022 में लगभग 1400 अवैध बेटिंग और जुए से जुड़ी वेबसाइट्स पर कार्रवाई की थी। इलेज़्ट्रॉनिज़्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगातार ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स पर निगरानी रख रहा है, जो गैरकानूनी तरीके से जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। इस कानून को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के नाम से भी जाना जाता है, ज़्योंकि इसे पिछले साल मंजूरी मिली थी। अधिनियम का मुज़्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों में पनप रही जुए की लत पर नियंत्रण पाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कई रियल मनी गेज़्स सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें नियंत्रित करना जरूरी माना गया।इस अधिनियम के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े गेमिंग ऐप्स और वेबसाइट्स पर रोक लगाई जाती है, ताकि देश में सुरक्षित और जिज़्मेदार ई-गेमिंग को प्रोत्साहित किया जा सके। ई-गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार के वास्तविक धन का लेन-देन नहीं होता और यह खिलाड़ियों की कौशल क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होते हैं।

हालांकि, कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स ई-गेमिंग या ई-स्पोर्ट्स की आड़ में अवैध जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देती हैं। नए ऑनलाइन गेमिंग एज़्ट के जरिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर सज़्ती से कार्रवाई की जा रही है, ताकि डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाया जा सके।

अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए भगवंत मान, गोलक बयान पर दी सफाई, कहा- हर फैसला मंजूर

नयी दिल्ली १५/०२ (संवाददाता): पंजाब के मुज़्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को सिख परंपराओं पर कथित टिप्पणियों के संबंध में श्री अकाल तज़्त साहिब के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। सचिवालय के समक्ष पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि तज़्त साहिब का निर्णय उन्हें सूचित किया जाएगा और वे इस निकाय के आगामी निर्णय का सज़्मान करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बयान का वीडियो %फर्जी% है और उन्होंने इसे फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराने का प्रस्ताव रखा।मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मिली सभी शिकायतों के जवाब में मैंने श्री अकाल तक़्त साहिब के समक्ष अपना पक्ष रखा है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

मशरूम

उगायें लाभ कमायें

आयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक को निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं

- मशरूम स्पान (बीज) उत्पादन
- माध्यम का उपचार
- माध्यम में स्पान मिश्रण
- मशरूम फसल प्रबंध

मशरूम स्पान (बीज) उत्पादन

आयस्टर मशरूम स्पान प्रमाणित प्रयोगशालाओं से ही प्राप्त करें स्पान बीज देखने में एकदम सफेद रेशेदार फफूंद से घिरा हो। यदि थैली के अंदर काले मटमैले या गहरे पीले धब्बे बनते हैं तो ऐसे बीज संक्रमित बीज होता है। इस प्रकार के बीज का चयन नहीं करना चाहिए. स्पान संभवतः ताजा हो, अधिक पुराना (1.5-2 माह) स्पान प्रयोग नहीं करना चाहिए.

माध्यम का उपचार

उपयुक्त माध्यम के रूप में धान की पैरा कुट्टी, गेहूं का भूसा या गेहूं+सोयाबीन का भूसा प्रयोग किया जा सकता है. इन माध्यमों को फसल कटाई के पश्चात अच्छे से सुखाना चाहिए माध्यम को ड़ेढ़ से दो इंच लम्बाई का काट ले फिर इस पैरे या गेहूं के भूसे को 14 घंटे के लिये स्वच्छ जल में भिगोकर रख दें। भूसे को निथारते हुए साफ-सुथरी ढलान वाली पक्की फर्स पर बिछाकर रखें।

माध्यम का निर्जीवीकरण

गर्म पानी द्वारा - उबले पानी में तैयार माध्यम को आधा घंटे तक भिगोकर रखें।

रसायन द्वारा- 10 किलो सूखा पैरा या गेहूं के भूसे को 100 लीटर पानी जिसमें 7.5 ग्रा. बाविस्टीन एवं 135 मि.ली. फार्मेलिन मिला हो इस पानी में 18-20 घंटे तक भिगोकर रखें.

माध्यम से स्पान मिश्रण

माध्यम में स्पान मिश्रण की अनेक विधियां हैं। जिसमें सम्पूर्ण मिश्रण विधि, तह विधि एवं समूह में दाने मिश्रण विधि प्रमुख हैं। इन तीनों विधियों में प्रथम दो विधि से स्पान मिश्रण प्रायः किया जाता है। स्पान को विभिन्न प्रकार की पारदर्शी थैलियों में भरा जाता है एवं इसे मशरूम उत्पादन कक्ष में स्थानान्तरित किया जाता है।

मशरूम फसल प्रबंधन

मशरूम फसल प्रबंधन मशरूम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. स्पान मिश्रित थैलियों को 15-20 दिन के लिये ऐसे कक्ष में रखा जाता है जहां मशरूम फफूंद की वानस्पतिक वृद्धि के लिये थोड़ा अधिक तापक्रम (28-30 डिग्री सल्स/कि. सूखा भूसा प्राप्त हो जाता है से.ग्रे.) होता है। 12 से 15 दिनों में मशरूम स्पान संपूर्ण माध्यम में फैल जाता है जिससे माध्यम सफेद दूधिया रंग का दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में थैलियों से पालीथिन फाड़कर अलग कर दें। पॉलीथिन हटाने के पश्चात मशरूम के कवकजाल से सम्पूर्ण माध्यम एक पिंडनुमा संरचना बन जाता है। पॉलीथिन हटाने 3-4 दिन पश्चात फफूंद की पिन हेड अवस्था दिखाई देने लगती है जिसमें छोटे-छोटे सफेद दाने माध्यम में दिखाई देते है। ये दाने 7 दिन में बढ़कर संपूर्ण छत्तानुमा संरचना बना लेते हैं।

तुड़ाई

जब ये छत्तानुमा संरचना के किनारे अंदर की ओर मुड़ने लगे तब हल्का सा मोड़कर इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। पहली फसल 22-25 दिन में प्राप्त हो जाती है। दूसरी और तीसरी फसल क्रमशः 5-7 दिन के अंतराल से प्राप्त हो जाती है इस तरह एक फसल चक्र में 45-50 दिन लग जाते हैं एवं 4-5 फसलें जुलाई से मार्च माह तक ली जा सकती है। मशरूम की एक फसल में 1 कि.ग्रा. सूखा माध्यम से 600 से 800 ग्राम ताजा मशरूम मिल जाता है।

ध्यान देने योग्य बिन्दु

1. मशरूम स्पान का माध्यम में पूर्ण फैलाव होने तक थैलियों में अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है परंतु थैली के काटने के पश्चात पिंडनुमा संरचना सदैव नम होना चाहिये। इसको नम रखने के लिये ठंड के मौसम में 2-3 बार एवं गर्म मौसम होने पर दिन में 4-5 बार स्प्रेयर से पानी की सिंचाई करना चाहिए.

आयस्टर मशरूम के अधिक उत्पादन हेतु ठंडा एवं नम वातावरण की आवश्यकता होती है। सीधा सूर्य का प्रकाश उत्पादन कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कक्ष में शुद्ध हवा का आवागमन अति आवश्यक हैं। इन मौसमीय परिस्थितियों के समुचित प्रबंधन से आयस्टर मशरूम की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है।

आयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक

- 10 कि.ग्रा. सूखा पैरा कुट्टी या गेहूं का भूसा लें।
- 100 लीटर पानी जिसमें 7.5 ग्राम बाविस्टीन (75 पीपीएम)+125 मि.ली. फार्मेलिन (500 पीपीएम), 10-16 घंटे भिगायें।
- भूसे से पानी निकालकर इतना सुखाना है ताकि गीला भूसा का वजन सूखे भूसे की तुलना में 2.5 से 3 फीसदी बढ़ जाये (68-70 प्रतिशत नमी)।

- स्वच्छ जगह में गीले भूसे में 30 ग्राम प्रति किलो कुट्टी के हिसाब से मशरूम स्पान मिलायें।
- स्पान मिश्रित पैरा कुट्टी को प्लास्टिक थैली में 4 किलो कुट्टी प्रति थैली के हिसाब से दबाकर भरें।
- थैली भरते समय थैली का एक चौथाई भाग खाली रखना है एवं थैली के निचले दोनों किनारों पर 5-7 छिद्र करें।
- थैली को ठंडे स्थान में लकड़ियों की रेकों में रखें या सुतली के माध्यम से लटकन विधि में एक के ऊपर एक 4-5 थैली लटका दें।
- 15-20 दिन बाद संपूर्ण थैली सफेद दूधिया रंग की दिखने पर पॉलीथिन थैली को हटाकर पिंडनुमा संरचना को सुतली से लटका दें।
- प्रथम तुड़ाई थैली काटने के 5-7 दिन बाद, दूसरी तुड़ाई प्रथम तुड़ाई के 5-7 दिन बाद तथा तीसरी तुड़ाई दूसरी तुड़ाई के 5-7 दिन बाद लें।
- एक फसल में 45-50 दिन तथा उपज 500-800 ग्राम ताजा मशरूम/किलो सूखा भूसा प्राप्त हो जाता है।

टिकाऊ खेती आज की आवश्यकता

किसी भी टिकाऊ खेती कोई एक नारा नहीं है बल्कि यक एक भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता है तभी हम मानव जाति भविष्य में पेट भर सकेंगे. अभी हाल ही के दशकों में संसार बहुत तेजी से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय एवं कृषि परिस्थिति की तौर पर बदला है. कारण बढ़ती हुई मानवीय भोजन, वस्त्र, मकान आदि की पूर्ति के लिए भूमि, जल एवं पर्यावरण का अत्याधिक शोषण हुआ जिससे टिकाऊ खेती की आवश्यकता महसूस हुई अर्थात् आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि में लगाने वाले साधनों का इस प्रकार सफल व्यवस्थित उपयोग किया जाना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास न होने पाये और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे. अतः टिकाऊ खेती को त्रिकोणीय रूप में रखा जा सकता है.

जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ को छू चुकी है जो 1991-2000 तक 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 2003-04 में 213.5 मिलियन टन तक पहुंचा अर्थात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से.

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

हमें आगे भी 21वीं सदी के बाद से खाद्यान्न में लगभग 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कायम रखनी होगी अन्यथा पूरा देश हमारा सूखा घोषित हो जायेगा जिससे की लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट होगी जो भविष्य के लिए प्रगति के उत्तम संकेत नहीं है.

भूमि-जल पर्यावरण

खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों शाकनाशियों अर्थात् रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में भूमि की दशा निश्चय ही खराब हुई है. जिससे की भूमि के लाभदायक कीट, केंचुए, जीवाणु इत्यादि नष्ट हुए हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों में भी भारी कमी हुई. अतः जीवांश खादों के प्रयोग से हम रोक सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकते है कई जंगल भी नष्ट किये गये सघन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है अर्थात् इसका दोहन कम किया जाए एवं इन्हें संरक्षित किया जाने का प्रयास करना नितांत आवश्यक है.

लाभ/खर्च अनुपात

हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सस्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. जिससे की हमारी भूमि में मृदा में तथा मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. यदि यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही तो भूमि एवं जल की उपादेयता समाप्त हो जायेगी और नई पीढ़ी का जीवन ही असुरक्षित हो जायेगा वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र बराबर कम होता जा रहा है. ऐसी परिस्थिति में हम टिकाऊ खेती का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है तथा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान व भविष्य दोनों में संतुलन हो. इस प्रकार की खेती का प्रयोग करके हम अपने भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित तो कर रही है बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा करके या उन्हें सुरक्षित बनाये रखने का कर्तव्य भी पूरी तरह निभा रहे हैं. अर्थात् हमें टिकाऊ खेती का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा हमें आर्थिक लाभ एवं भारत सरकार को पूर्णतः उत्पादन से लाभ प्राप्त हो सके.

कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिए उत्पादकता टिकाऊपन तथा समानता की बहुत जरूरत है हमें भारत में भी बदलते पर्यावरण में कृषि निर्वाह की प्राथमिकता देनी अनिवार्य आवश्यकता है. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हम आर्थिक दृष्टि से कारगर, पर्यावरण की दृष्टि त्रुटीहीन सामयिक दृष्टि से सुसंगत प्रौद्योगिकी जो कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पाद दे सकें.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकाऊ खेती मानव जाति को निरंतर खुशहाली प्रदान का वचन देती है.

टिकाऊ खेती का महत्व

टिकाऊ खेती का महत्व सबसे अधिक वर्तमान खेती की प्रणालियों, तरीकों एवं समस्याओं को सुधारने में है. टिकाऊ खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं मृदा, जल, ऊर्जा, वन-विकास एवं जंगली पशुओं की सुरक्षा या इन्हें सुरक्षित रखने से है. टिकाऊ खेती में इनके प्रबंधन पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है. कई प्रकार की उत्पन्न समस्याओं जैसे- सौर ऊर्जा का उचित प्रयोग, वातावरण प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरण का संतुलन डगमगाना इत्यादि समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना ही इसमें निम्न विषय है अर्थात् भविष्य में टिकाऊ खेती के माध्यम से इन समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है.

टिकाऊ खेती का लाभ

- पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाये रखने में टिकाऊ खेती का प्रमुख कार्य है.
- वातावरणीय प्रदूषण कम होता है.
- लगाई फसलों की उत्पादन लागत कम आती है.
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित प्रकार से करते हैं.
- टिकाऊ खेती में भूमि, जल, ऊर्जा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करते है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग एवं दोहन ध्यान रखकर कर सकें.
- ओरोबंकी परजीवी को हाथ से उखाड़ कर या सावधानी से साधारण कसी से निराई-गुड़ाई द्वारा जमीन के ऊपर के तने को काटकर बीज बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिये।
- यदि बीज बन गये हों तो पौधों को सावधानी से निकालना चाहिये जिससे बीज भूमि में नहीं मिलें।
- जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रकोप होता है वहां सरसों की फसल ट्रेप क्रोप के रूप में बोनी चाहिये। 30 से 40 दिन में परजीवी के पौधे बाहर निकलते दिखाई दें तो नवम्बर के अंत में गहरी जुताई करके सरसों सहित इसके भूमिगत तने को नष्ट कर देना चाहिये। इसके बाद अन्य फसल बो देना चाहिये।
- जब तक इसका पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता सरसों के स्थान पर अरण्डी की फसल बोयें, क्योंकि अरण्डी एक वर्षीय फसल है इससे परजीवी को रोकने में मदद मिलेगी।
- कुछ पौधों जैसे मिर्च के बोने से ओरोबंकी के बीजों का अंकुरण हो जाता है लेकिन मिर्च की फसल पर इस परजीवी से कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार भूमि में मौजूद ओरोबंकी के बीजों को अंकुरित कर इस फसल का ट्रैप फसल के रूप में प्रयोग कर परजीवी के पौधों को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार मिर्च, सरसों फसल चक्र अपनाने से इस परजीवी का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जायेगा।
- लम्बे समय तक फसल चक्र अपनाकर इसकी आता को रोका जा सकता है।
- पौधों की भूमि की सतह के पास 25 प्रतिशत ताम्र घोल का छिड़काव करने से परजीवी नष्ट किये जा सकते हैं।
- ओरोबंकी पौधों पर सोयाबीन के तेल की 2 बूंदे डाल देने से पौधा मर जाता है।
- सरसों की आग्या रोगरोधी किस्म दुर्गामणि की बुवाई करें।

दूध के साथ रेशम उत्पादन

मिल्क विथ सिल्क सिद्धांत की जरूरत और महत्व

भारत के कई इलाकों में सिंचाई की सुविधाएँ सीमित मात्रा में होने से 50 प्रतिशत से ज्यादा खेती बारानी है। यह सर्वविदित है कि पिछले कुछ वर्षों से अनियमित मानसून, अमौसमी बरसात, कठोर जलवायु तथा अन्य कई कारणों से बारानी खेती बिना भरोसे की तथा नुकसानमंद साबित हो रही हैं। इससे किसानों में निराशा आर्थिक नुकसान के कारण आत्महत्या तक हो रही हैं। इस स्थिति से उबरने का एक उपाय हैं खेती से जुड़े पूरक व्यवसाय शुरू करना और उन्हें ज्यादा प्रभावी तथा ज्यादा फायदेमंद बनाने हेतु दो या तीन पूरक व्यवसायों को एक साथ करना जैसे दुग्ध व्यवसाय और रेशमकीट पालन एक साथ करना जो एक-दूसरे के पूरक हैं।

दुग्ध उत्पादन हेतु पशुपालन तथा रेशम कीट पालन हेतु मलबेरी की काश्त करना एक-दूसरों के कई तरह से पूरक हैं। पशुओं को दूध उत्पादन हेतु पौष्टिक चारा चाहिए जो उन्हें मलबेरी की पत्तियों से मिलता हैं। इसके अलावा मलबेरी की पत्तियाँ जायकेदार पाई गई। उनकी पाचकता 70 से 90 च् पाई गई। उनमें खनिज लवण 25 प्रतिशत तक पाये गये जो दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा पशु के स्वास्थ्य एवं प्रजनन क्षमता बरकरार रखने हेतु अत्यंत उपयुक्त हैं।

एक गाय को उसके शरीर पोषण हेतु रोजाना 7 ग्राम कैल्शियम तथा 7 ग्राम फॉस्फोरस आवश्यक होता हैं जबकि मलबेरी की पत्तियों में करीब 1.8 से 2.4 प्रतिशत कैल्शियम तथा 0.14 से 0.24 प्रतिशत फास्फोरस पाया गया हैं। इसका मतलब है कि अगर मलबेरी की पत्तियाँ भरपूर मात्रा में दुधारू पशु को खिलाई जाये तो उनके दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी इसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि खुराक और मलबेरी को पत्तियां अनुक्रम 60:40 तथा 25:75 प्रतिशत इस अनुपात में खिलाने पर गायों का दूध उत्पादन 13.2 और 13.8 लीटर प्राप्त हुआ जबकि सिर्फ खुराक खिलाने पर 14.2 लीटर था। इसका मतलब यह हुआ की मलबेरी की पत्तियाँ खिलाने से दूध उत्पादन में ज्यादा कमी नहीं आई बल्कि खुराक की मात्रा कम लगने से उसके पोषण खर्च में कमी आई यानि मलबेरी की पत्तियां खिलाने से दूध उत्पादन का धंधा किफायती होता हैं।

रेशम कीटों को डाली हुई मलबेरी की जो पत्तियां बाकी रह जाती हैं वो पत्तियाँ, डालियाँ दुधारू पशुओं को खिलाया जाये तो वह बरबाद होने से बच जाता हैं। कुछ स्थानों पर रेशम की इल्लियों के अपशिष्ट पदार्थ पर नमक का घोल डालकर वह दुधारू पशुओं को खिलाया जाता हैं।

इस प्रकार रेशम कीट पालन तथा दुग्ध व्यवसाय का आपस में घनिष्ट नाता जोड़कर दोनों ही व्यवसाय एक साथ एक ही खेत पर कर सकते हैं। इसमें जो मजदूर होते हैं उनका उत्कृष्ट इस्तेमाल होता हैं. रेशम कीटों द्वारा कोष निर्माण होने पर उन्हें बेचकर पैसा प्राप्त होता हैं। इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय से दूध, खाद तथा बछड़े बेचकर अधिक धन प्राप्त होगा और इस प्रकार किसान भाईयों को कमाई के दो स्त्रोत प्राप्त होंगे जिससे ज्यादा आर्थिक सम्पन्नता का लाभ होगा।

रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण, जानकारी, तांत्रिक मार्गदर्शन, रेशम उद्योग, संचालनालय से प्राप्त होते हैं तथा दुग्ध व्यवसाय के विषय में जानकारी प्रशिक्षण तथा तांत्रिक मार्गदर्शन हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित पशुपालन एवं दुग्ध शास्त्र विभाग आदि जगह से प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान रहे, पूरक व्यवसाय के बिना किसान भाईयों की सही मायने में उन्नति नहीं हो सकती अतः पूरक व्यवसाय अवश्य अपनाएं और अपनी आर्थिक उन्नति हासिल करें.

मलबेरी के पत्तियों का रासायनिक संगठन

शुष्क पदार्थ	25.0 %
कच्चा प्रोभूजिन	20.0 %
कुल प्रोभूजिन	-
लायसिन	5.30 %
मिथियोनाईन	1.78%
फिनायल नाईन	4.34 %
ल्युसीन	6.89 %
आयसोल्युसीन	4.74 %
थ्रियोनीन	4.25%
हिस्टीडीन	3.56%
वेलीन	5.16 %
आर्जिनाईन	4.52%
अस्पॉरमीन	8.26%
ग्लुटॅमाइन	11.46%
सेरीन	4.2%
ग्लायसीन	5.34 %

कलिंग समाचार

संपादकीय

सोमवार 16 फरवरी 2026

देश की सुरक्षा और सच-झूठ की परीक्षा

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर सियासी घमासान अब सच और झूठ की परीक्षा में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस किताब की प्रति पिछले ह ते ही संसद में लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह किताब देंगे, ताकि वे खुद उन बातों और तथ्यों को पढ़ सकें, जिन्हें लोकसभा में पढ़ने से राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन नरेन्द्र मोदी इसके बाद लोकसभा में पहुंचे ही नहीं और न ही राहुल गांधी से उनका सामना हुआ। हालांकि यह एक अच्छा मौका नरेन्द्र मोदी के पास था, जब वे एक साथ अपनी देशभक्ति, बहादुरी और 56 इंची सीने की सच्चाई देश-दुनिया को दिखा देते। राहुल गांधी का कहना है कि नरेन्द्र मोदी एक किताब से डर गए, क्योंकि इसमें चीन के घुसपैठिया अभियान की हकीकत बयां की गई है। श्री मोदी चाहते तो राहुल गांधी से ये किताब लेकर साबित कर देते कि वे डरे हुए नहीं हैं और जो कुछ उस किताब में लिखा है उसे भी पढ़ लेते। अगर कुछ गलत लिखा है तो उसकी सच्चाई बता देते, इससे उनका ही हाथ ऊंचा होता। लेकिन बजाए इतना सीधा सा काम करने के, अब इस मामले को कानूनी पचड़े में उलझा दिया गया है। अब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब की सॉ ट कॉपी के ऑनलाइन प्रसारित होने पर एफ़आईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है, हमने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से यह अभी अप्रकाशित है। स्पेशल सेल में एफ़आईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है। गौरतलब है कि किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है कि 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के दौरान जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य नेताओं को जानकारी दी कि, %चीनी टैंक आ रहे हैं, तो लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। करीब ढाई घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया- %जो उचित समझो, वो करो। राहुल गांधी इसी पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, मुझे यक़ीन है कि यह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई।% उन्होंने राहुल गांधी से कहा, जो किताब का दावा कर रहे हैं, उसे सदन में पेश करें, हम देखना चाहते हैं। सरकार द्वारा ऐसी किसी किताब के छपे होने के दावे को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने 4 फरवरी को संसद परिसर में किताब की प्रकाशित प्रति दिखाई और पत्रकारों से कहा, देखिए, किताब है, सरकार कह रही है कि किताब नहीं है। बता दें कि फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा है। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। किताब में उनकी 40 साल की सेवा, सिक्किम में चीन से पहला आमना-सामना, गलवान संघर्ष, पाकिस्तान के साथ सीजफायर आदि का ज़िक्र है। किताब 448 पेज की है और अप्रैल 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली। बहरहाल, दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच-पड़ताल में करेगी कि आख़िर यह किताब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन लोगों तक कैसे पहुंच रही है। किताब को प्रकाशित करने की जरूरी मंजूरी रक्षा मंत्रालय से अभी नहीं मिली है। इसलिए यह लीक या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली पुलिस के पास और कोई जरूरी काम बचे ही नहीं है। हालांकि सोमवार को ही कम से कम पांच हत्याओं के मामले दिल्ली में घटित हुए हैं, इसके अलावा चोरी, छीना-झपटी, झगड़े-फसाद, लड़कियों की सुरक्षा जैसे अनगिनत मामले हैं, जिन्हें संभालने या कम करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है। मगर इन सबको छोड़कर अमित शाह के गृह मंत्रालय ने अपनी पुलिस को इस काम में लगाया है कि किताब का पीडीएफ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। इस बीच किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की भी सफाई आई है।

जंगल कैसे बचाते हैं पातालकोट के भारिया?

बाबा मायाराम

तामिया के पास पातालकोट प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। गहराई में बसा यह इलाका जंगल और पहाड़ से घिरा है। यहां मु यत- गोंड और भारिया आदिवासी रहते हैं, जो पीढ़ियों से परंपरागत देसी बीजों के साथ खेती करते आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे परंपरागत बीज लुप्त होने के कगार पर हैं। यहां कुछ समय पहले निर्माण संस्था ने देसी बीज बचाने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में आने वाला पातालकोट, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। पाताल की तरह गहराई वाली जगह और कोट यानी दुर्ग, दीवारों से घिरी है, यही है पातालकोट। यहां दीवार का अर्थ पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी गहराई में बसे हुए हैं 12 गांव और उनके ढाने यानी मोहल्ले। यहां भारिया आदिवासियों का निवास है, मैं यहां कई बार गया हूं। इस कॉलम में आप से बात करना चाहता हूं कि कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता क्या है, जिससे हम उनकी सरल व सहज जीवनशैली समझ सकें।

तामिया के पास पातालकोट प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। गहराई में बसा यह इलाका जंगल और पहाड़ से घिरा है। यहां मु यत- गोंड और भारिया आदिवासी रहते हैं, जो पीढ़ियों से परंपरागत देसी बीजों के साथ खेती करते आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे परंपरागत बीज लुप्त होने के कगार पर हैं। यहां कुछ समय पहले निर्माण संस्था ने देसी बीज बचाने की कोशिश की है। मुझे यहां कई बार जाने का मौका मिला है। एक बार मुझे स्कूली बच्चों के साथ जंगल में पेड़ पौधे, खाद्य पदार्थ जानने-पहचानने और वन खाद्य चखने का मौका मिला मिला। कोदो का भात, और जंगली हरी पत्तीदार भाजियां भोजन में शामिल थीं। हम बच्चों के साथ जंगल में घूमे थे। साथ में गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे, जो पेड़-पौधे से स्थानीय नाम व उनके गुणधर्म बता रहे थे। इससे बच्चों को उनके आसपास के जंगल और जैव विविधता को जानने का मौका मिल रहा था। निर्माण संस्था के नरेश विश्वास ने बहुत मेहनत से वन खाद्यों के बारे में कुछ पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की हैं।,द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - मिशन-500 या कूटनीतिक आत्मसमर्पण? भारत-अमेरिका डील के अनकहे पहलू इसी प्रकार, मुझे यहां एक जैव-विविधता प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका मिला था। यह निर्माण संस्था द्वारा आयोजित थी, जो इस इलाके में देशी बीजों की जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रदर्शनी में कई तरह के अनाज जैसे तुअर दाल, डोंगरा सावां, भदेली, बेउरी, कोदो, मडिया, करिया कंगनी, कुसमुसी,जगनी, ज्वार, सिकिया, रजगिरा, बाजरा, काली कुरथी, दूधिया मक्का थे। इसके अलावा, बल्लर, बरबटी, लौकी, गिलकी, लाल सेमी इत्यादि के बीज शामिल थे। इन अनाजों से कई तरह के व्यंजन बनाकर भी टेबल पर सजाए गए थे। जैसे कुटकी पापड़, सावां चटली, कोदो पापड़ी, मड़िया पापड़ी, मड़िया सेव, कोदो चाटला, बाजरा के बड़े, महुआ हलवा, सावां के लड्डू, कोदो के लड्डू, ज्वार के लड्डू, महुआ का भुरका, कोदो पुलाव, कुटकी खीर, सावां की खिचड़ी, ज्वार का भात, मड़िया का हलवा इत्यादि।

गैलडुब्बा गांव की महिलाओं ने बतलाया था कि, %यहां की ज़मीन पथरीली है, इसलिए इसमें कुटकी, सांवा, मक्का, बाजरा और कांग की फसल होती हैं। हम मक्का और ज्वारी का भात पकाकर खाते हैं। कम-ज्यादा बारिश होने पर भी फसलें पक जाती हैं। हम पीढ़ियों से ऐसी पारंपरिक खेती करते आ रही हैं।% वे आगे कहती हैं कि इस जमीन में हमारे पुरखों के बीज ही काम आते हैं। यह अनाज कम पानी में भी पक जाते हैं। महिलाएं इस खेती में अपनी भागीदारी निभाती हैं, बीज बोने से लेकर, निंदाई-गुड़ाई-कटाई तक और बाद में बीजों को संभालने का काम करती हैं। परिवार के सदस्यों को भोजन पकाकर भी देती हैं।बुलेट ट्रेन गैलडुब्बा गांव के भगलू चलथिया बताते हैं कि आदिवासियों का जीवन जंगल और खेती पर निर्भर है। होली के आसपास महुआ की बिनाई 15 दिन तक चलती है। इसके बाद, चिरौंजी भी एक पखवाड़े तक बीनते हैं। जब 15 जून के आसपास बारिश आ जाती है तो खेती-किसानी शुरू हो जाती है। खेतों की जुताई, बौनी-बखरनी होती है। दिवाली के समय फसलों की निंदाई-गुड़ाई करनी पड़ती है।

बुलेट ट्रेन गैलडुब्बा गांव के भगलू चलथिया बताते हैं कि आदिवासियों का जीवन जंगल और खेती पर निर्भर है। होली के आसपास महुआ की बिनाई 15 दिन तक चलती है। इसके बाद, चिरौंजी भी एक पखवाड़े तक बीनते हैं। जब 15 जून के आसपास बारिश आ जाती है तो खेती-किसानी शुरू हो जाती है। खेतों की जुताई, बौनी-बखरनी होती है। दिवाली के समय फसलों की निंदाई-गुड़ाई करनी पड़ती है। वे आगे बताते हैं कि आदिवासी जंगल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस तरह बच्चों की परवरिश जतन से करनी पड़ती है, उसी तरह पेड़ों की और जंगल की परवरिश करनी पड़ती है। हम समय-समय पर पेड़ों की कटाई-छंटाई करते रहते हैं। उनकी आड़ी-टेढ़ी टहनियां काटते हैं। पेड़ों के नीचे बीजों से जो पौधे बनते हैं, उनकी देखरेख करनी पड़ती हैं।

वे आगे बताते हैं कि आदिवासी जंगल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस तरह बच्चों की परवरिश जतन से करनी पड़ती है, उसी तरह पेड़ों की और जंगल की परवरिश करनी पड़ती है। हम समय-समय पर पेड़ों की कटाई-छंटाई करते रहते हैं। उनकी आड़ी-टेढ़ी टहनियां काटते हैं। पेड़ों के नीचे बीजों से जो पौधे बनते हैं, उनकी देखरेख करनी पड़ती हैं। जिनके बीज से पौधे उगते हैं, उनके बीज जंगल में फेंकते हैं, जिससे वे बारिश में अंकुरित हों, और फले-फूले। वे आगे बतलाते हैं कि इसी प्रकार, पानी के स्रोतों व नदियों की भी साफ-सफाई चलती रहती हैं। यहां पनिया झरना है, उसकी नियमित सामूहिक रूप से साफ-सफाई करनी होती है। इनके किनारे के पेड़-पौधों व झाड़ियों की देखरेख करनी होती है। यह पेड़-पौधे व झाड़ियां पानीदार होते हैं, जिससे नदी में पानी बहता रहता है, वह सदानीरा बनी रहती है। डोंगर (पहाड़) से दुधी और गायनी नदी निकली हैं। दुधी, नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है। हालांकि कई कारणों से अब यह बारहमासी नदियां सूखने लगी है, और बरसाती नदी बन गई है। भगलू चलथिया के अनुसार, %अगर जंगल रहेगा तो आदिवासी भी रहेगा, अगर जंगल कट जाएगा तो आदिवासी भी जंगल के आसपास नहीं रह पाएगा, वह कैसे जियेगा? इसलिए उनके बुजुर्ग कहते हैं कि जंगल को कभी काटना नहीं है। उन्होंने बताया कि जंगल को आग से बचाने के लिए कोशिश की जाती है। गर्मी के दिनों में आग की घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं इसलिए महुआ फूल बीनने के लिए उसके नीचे के पत्तों को एक जगह एकत्र करके जलाते हैं, जिससे जंगल में आग न लगे, न फैले। अगर आग लग भी जाती है तो वे भी आग बुझाने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि जंगल से हमारा मां-बेटे का रिश्ता है। जितनी जरूरत है उतना ही जंगल से लेते हैं। नई पीढ़ी को भी जंगल बचाकर रखना है। हमें पेड़ों की छांव चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ रहेंगे तो पानी भी मिलेगा। जंगल से खाने के लिए पौष्टिक कंद-मूल, हरी भाजियां व फल-फूल मिलते हैं। पातालकोट में तो अब भी वन कलेवा (जंगल के कांदा व फल का नाश्ता) करने का चलन है। निर्माण संस्था के नरेश विश्वास ने बताया कि पहले पातालकोट में बहुत गिद्ध हुआ करते थे। यह गिद्धों का घर माना जाता था। कोई मवेशी मर जाता था, तो गिद्ध खा जाते थे। स्वच्छ व साफ-सुथरा वातावरण करने का यह प्राकृतिक तरीका था। उन्होंने बताया कि जलवायु बदलाव के दौर में परंपरागत पौष्टिक अनाजों की खेती बहुत उपयोगी हो गई है। इनमें कम पानी व प्रतिकूल मौसम में पकने की क्षमता होती है। देसी बीजों की खेती स्वावलंबी होती है और इसमें कम मेहनत भी लगती है। किसी भी तरह के रासायनिक खाद व कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें किसी भी तरह की मशीन जैसे ट्रेक्टर आदि का इस्तेमाल भी नहीं होता, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। यानी इसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है, यह खेती टिकाऊ है, यह पूरी तरह जैविक व पौष्टिक अनाजों की खेती है। लागत खर्च नहीं के बराबर है। अगर इसमें उत्पादन कम भी हो जाए तो भी किसान को घाटा नहीं होता। इस खेती से जमीन का उर्वरता बनी रहती है। कुल मिलाकर, यह कहना उचित होगा कि पारंपरिक स्वावलंबी खेती के साथ आदिवासियों ने परंपरागत ज्ञान को भी बचाया है। अपनी पारंपरिक व्यवस्था को कायम रखकर प्रकृति की पूजा और प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन का उनका अपना तरीका है, इससे पर्यावरण की रक्षा भी होती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के दौर में परंपरागत बीजों की खेती महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी के लिए विरासत है, जिसे सहेजा जा रहा है। और यह सब वे आपस में एकजुटता, सामूहिकता और एक-दूसरे की मदद से कर पाने में सक्षम हैं। क्या हम इनसे कुछ सीखना चाहेंगे?

दो व्यापार समझौते और तीन चुनौतियां

अरविन्द मोहन

करोड़ों गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी और काम के तय घंटे जैसी बुनियादी चीजें देना भी उसका काम है। और रोजगार भी तभी बढ़ेंगे जब निवेश का तंत्र सुधरेगा। असल में यह खाए, पिए अघाए लोगों का बजट है, अच्छी हालत में भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करने की जगह चीजों को वैसे ही चलाने देने की सोच का अभाव है, कुछ न करके भी संतुष्ट रहने का बजट है।

आखिर अमेरिका से भी व्यापार संधि हो गई और सारी बारीकी सामने नहीं आई हो तब भी यह नतीजा निकालने में हर्ज नहीं है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाले प्रावधान इसमें हैं और 18 फीसदी सीमा शुल्क पर भारतीय माल के अमेरिका प्रवेश का मतलब हमारा व्यापार बढ़ना ही होगा। एक नई बात यह हो सकती है की कुछ अमेरिकी/विदेशी उत्पादक अमेरिका में ही अपना ज्यादा माल बेच सकने की सहूलियत के लिए भारत में अपना प्रोडक्शन बेस बनाएं। अमेरिकी संधि तो बजट के अगले दिन हुई पर यूरोपीय संघ से खुले व्यापार की संधि भी तीन- चार दिन पहले हुई थी। उसके प्रावधान भी यही स्थिति बनाते हैं और यही चीजें इन संधियों का सबसे धनात्मक पक्ष है। अब अमेरिका से समझौते की घोषणा भले दो तारीख को हुई हो लेकिन अधिकांश शर्तों पर सहमति बनाने की चर्चा बिहार चुनाव के पहले से हो रही थी। और तो और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तीन दिन पहले यह कह दिया था कि यह समझौता अब हो जाने को ही है। इस प्रसंग को लंबा खींचने के पीछे यह बात दिखाने की मंशा है कि बजट की तैयारियों के क्रम में इन दो बड़ी संधियों का आधार तैयार था और कम से कम इस बातचीत में शामिल लोगों को तो प्रावधानों की भी लगभग पूरी स्थिति का पता होगा।

लेकिन निर्मला सीतारमन के नौवें बजट में इस संधियों के फलितार्थ से संबंधित कोई तैयारी नहीं दिखती। यूरोपीय संघ और अमेरिका हमारे पशुपालन और खेती को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के लिए दबाव बना रहे थे और इनमें से काफी बातें मान ली गई हैं। कार, शराब से लेकर अनेक अ

ौद्योगिक उत्पाद का आयात सस्ता होकर हमारे अपने उत्पादन और खपत के परिदृश्य को बदलेगा। बजट में कृषि और पशुपालन या मत्स्य और कुक्कुटपालन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो आगे आने वाले प्रभाव में हमारे किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा कर सके। हम जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में खेती और डेयरी का कारोबार भारी सब्सिडी पर चलता है। ऐसे में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, जेनेटिक फसलों और खली के धंधे पर ही नहीं दूध, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों पर असर होगा लेकिन वित्त मंत्री ने उसकी चिंता अगले बजट के लिए छोड़ दी है। वे इस बजट को जाने किस आधार पर युवाओं का और नये भारत के निर्माण का बजट बता रही हैं।

इससे भी ज्यादा जिस चीज की चिंता करनी चाहिए थी वह है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ठिकाना बनाने की तैयारी। ये दोनों व्यापार सन्धियां हमारे यहां से तैयार माल को यूरोप और अमेरिका में भेजने का रास्ता सुगम करेंगी। फिर सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर के लिए ही नहीं, सारे औद्योगिक उत्पादों और उपभोक्ता मशीनरी के निर्माण और एसे बलिङ्ग कारोबार की राह इससे खुलने वाली है। इस बीच यह भी हुआ है कि ट्र प की नीतियों और वैश्विक वित्त बाजार में अनिश्चितता के चलते दुनिया भर की पूंजी विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ मुड़ गई है। और तो और वहां भी सोना-चांदी में निवेश को सुरक्षित और बढ़ने वाला मानने का चलन बढ़ा है। उनके यहां के निवेश में पांच से बारह फीसदी तक की वृद्धि हुई है जबकि हमारे यहां से बड़ी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में कमी आई है। विदेशी पूंजी की जगह देसी पूंजी ने कुछ समय तक मोर्चा संभाला लेकिन अब उसकी क्षमता की सीमा आ गई है, यह हर आदमी महसूस कर रहा है।

बाजार से पूंजी का पलायन रोकने और नई पूंजी को आकर्षित करने वाले कदम उठाने की दरकार है लेकिन निर्मला जी का बजट इस बारे में मौन हो गया है। संरचना क्षेत्र में निवेश अच्छा होता है लेकिन हर जानकार बताता है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश इस क्षेत्र में कर चुके हैं।

पूंजी का पलायन रोकने और नए निवेश को आकर्षित करने जैसा ही इमरजेंसी वाला काम डालर और प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का धराशायी होना रोकने का है। ऐसी ही आपात जरूरत सर्राफा बाजार के भूचाल को संभालने की है। चांदी भारी सट्टेबाजी की चीज बन गई है और शादियों के मौसम में आम आदमी सोना तो दूर चांदी तक खरीदने की स्थिति में नहीं है और उधर सट्टेबाज माल बनाकर लाल होते गए हैं। एक किलो चांदी की कीमत में एक दिन में अस्सी हजार तक की गिरावट और चढ़ान तो बिना सट्टेबाजी संभव ही नहीं है। और अगर चीन या कोई भी और देश सोना चांदी खरीद कर जमाखोरी कर रहा है तो उसका भी उपाय ढूंढा जाना चाहिए। शेयर बाजार का यही हाल है और बजट के दिन की उसकी दो हजार अंकों की गिरावट को बजट से निराशा मान सकते हैं लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा एक कंपनी को नोटिस देने भर से बाजार लाखों करोड़ के मूल्य गंवा दे यह तो सट्टेबाजों का नहीं उनकी गिरोहबाजी से ही संभव है। रुपया रोज गोते खा रहा है और साल भर में छह फीसदी तक नीचे आ गया है।

बजट में इन क्षेत्रों का जिक्र ही नहीं है और प्रतिभूति कारोबार टैक्स बढ़ाकर ऐसा हंगामा मचा दिया गया कि हर आदमी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह क्या बला है। और जो स्थिति समझते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि इस उपाय से बाजार को क्या फायदा होगा? शायद सरकार महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ने न देने की मंशा को ऊपर रख रही है। उसे जीडीपी की दर और महंगाई दर की चिंता सबसे ज्यादा है। वह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर पर इठला रही है। उसने पिछले बजट में आयकर नियमों में जो बदलाव किए हैं और जो इस बार अप्रैल से लागू होंगे, उनको फाइनल मान लिया है।

उसने जीएसटी दरों में जो बदलाव किये उनके बाद कर के ढांचे में मामूली करेक्शनों को छोड़कर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। वह भूल गई है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना उसी का काम है और दस साल से ज्यादा समय से टल रहा है। अभी के बढ़े टैक्स अपने लोगों से हर साल तीन लाख करोड़ ज्यादा वसूल कर उसके बटुए में पहुंचा देते हैं।

वह भूल गई है कि देश में आधे कामगार खेती से जुड़े हैं और सस्ते विदेशी आयात के बाद उन सबके जीवन पर कम ज्यादा असर होगा ही। करोड़ों गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी और काम के तय घंटे जैसी बुनियादी चीजें देना भी उसका काम है। और रोजगार भी तभी बढ़ेंगे जब निवेश का तंत्र सुधरेगा। असल में यह खाए, पिए अघाए लोगों का बजट है, अच्छी हालत में भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करने की जगह चीजों को वैसे ही चलाने देने की सोच का अभाव है, कुछ न करके भी संतुष्ट रहने का बजट है।

विविध समाचार

हिमाचल में गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, मची चीख–पुकार, 8 लोगों की दर्दनाक मौत

सिरमौर १५/०२ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार दोपहर बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। हरिपुरधार इलाके के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के

अनुसार, यह प्राइवेट बस कुपवी से राज्य की राजधानी शिमला जा रही थी। हरिपुरधार के पास पहुंचते ही बस अचानक सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। बस के खाई में गिरते ही वहां चीख–पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस के आने से पहले ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोग अपनी पीठ पर लादकर घायलों को सड़क तक लाते दिखे। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि हादसे में 8 लोगों की जान गई है। उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एसपी ने कहा, "मैं खुद मौके के लिए रवाना हो गया हूं। पुलिस और बचाव टीमें घायलों को खाई से निकालने में जुटी हुई हैं।" हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। गंभीर रूप से घायल पांच मरीजों को इलाज के लिए संगड़ाह, ददाहू और मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया जा रहा है। वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने नाहन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आप ने मनरेगा योजना को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने के विरोध में किया विशाल प्रदर्शन

नाभा १५/०२ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को नाभा के पटियाला गेट पर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला जला कर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए आप विधायक गुरदेव सिंह देव मान ने कहा कि केंद्र अगर चाहे तो मनरेगा का नाम बदल सकता है लेकिन इसकी नीति और मंशा में पूर्ण बदलाव अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा की आत्मा ही बदल दी है। इसकी नई नीतियों का मकसद गरीबों को कुचलना, उनकी रोजी–रोटी छीनना और उन्हें और गरीबी में धकेलना है। उन्होंने केंद्र पर उन लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देश को बनाया है। विधायक ने केंद्र के मनरेगा फंडिंग का 40 फीसदी बोझ राज्यों पर डालने के फैसले का भी कड़ा विरोध करते हुए इसे "पूरी तरह से गैर–वाजिब और संघवाद विरोधी" करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य यह अतिरिक्त बोझ कैसे झेलेंगे। यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब विधानसभा ने स्पष्ट रूप से केंद्र से मांग की है कि मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए और ये गरीब विरोधी बदलाव वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, अमन अरोड़ा और पूरी पार्टी मनरेगा मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आप अनुसूचित जाति शाखा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जीपी ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी मनरेगा के बचाव में प्रदेशव्यापी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आप पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रही है। कल हमने जालंधर में प्रदर्शन किया था, आज नाभा में और यह आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज होगा। उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर लगातार हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों पर तीन काले कृषि कानून थोपे गए थे। फिर संविधान को कमजोर करने की कोशिशें हुईं। अब मनरेगा के नए कानूनों के जरिए कामकाजी महिलाओं और गरीब परिवारों पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। हम इस बेइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक केंद्र बदलाव वापस नहीं लेता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जहरीला पानी पीने को मजबूर है जनता, अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

चंडीगढ १५/०२ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को हरियाणा में पेयजल संकट को लेकर बीजेपी सरकार को तथ्यों और सरकारी आंकड़ों के आधार पर कठघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 11 सालों से भी ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार हरियाणा में काबिज है, लेकिन आज भी प्रदेश की बड़ी आबादी गंदा, दूषित और जानलेवा पानी पीने को मजबूर है। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि 11 साल का साबित हुआ सरकारी धोखा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आज भी हरियाणा के 3500 से ज्यादा गांवों में पानी पीने योग्य नहीं है। कई जिलों में पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम की मात्रा तय मानकों से कई गुना ज्यादा पाई गई है। सोनीपत में आर्सेनिक, दक्षिण हरियाणा में फ्लोराइड, कई जिलों में नाइट्रेट और यूरेनियम की मौजूदगी सरकार की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के मानकों के अनुसार पीने के पानी में टीडीएस की सुरक्षित सीमा 200– 300 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, जबकि हरियाणा के कई शहरों और गांवों में लोगों को 1000 से 2000 टीडीएस तक का पानी पिलाया जा रहा है। यह पानी धीरे–धीरे शरीर को बीमार करता है और ब्लड प्रेशर, पथरी, पेट की गंभीर बीमारियां, हड्डियों की कमजोरी और कैंसर तक का खतरा पैदा करता है। अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार अमृत योजना के नाम पर करोड़ों और जल जीवन मिशन के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके ठीक उलट है। ये योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चरखी दादरी और बाढड़ा जैसे इलाकों में 90 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी करीब 1 लाख लोग प्यासे हैं। हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और अंबाला में आज भी 50 से 60 साल पुरानी पाइपलाइनें चल रही हैं, जो सीवर नालों के ऊपर से गुजरती हैं और सीधे गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा रही हैं। रेवाड़ी में तो हालात इतने खराब हैं कि एसटीपी प्लांट से ही दूषित पानी छोड़े जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल

का दावा किया गया, लेकिन सरकारी सर्वे खुद बताते हैं कि कई जिलों में लोगों को रोजाना न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति पानी भी नहीं मिल पा रहा। कहीं कवरेज आधा है तो कहीं एक–तिहाई से भी कम। इसका मतलब साफ है कि योजनाएं कागजों में पूरी हैं, जमीन पर पूरी तरह फेल। मतलब साफ है, कागजों में योजना पूरी, जमीन पर जनता बेहाल। अनुराग ढांडा ने कहा कि यह सवाल मुख्यमंत्री नायब सिंह से सीधा पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से ज्यादा समय तक बीजेपी सरकार ने आखिर किया क्या? जब सरकार को पता है कि पानी के सैंपल फेल हो रहे हैं, तब भी न नियमित क्लोरीफिकेशन, न पाइपलाइन बदलने की रफ्तार और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। क्या बीजेपी सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? उन्होंने कहा कि बीजेपी का 11 सालों का शासन हरियाणा की जनता के लिए जहर साबित हो रहा है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी अगर लोगों को पीने का साफ पानी न मिले, तो यह सरकार के पूरी तरह फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है। अनुराग ढांडा ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत हरियाणा के हर शहर और गांव में शुद्ध, सुरक्षित और मानक के अनुसार पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी।

जालंधर कैंट विधानसभा मे भाजपा के पक्ष में उमड़ा जनसैलाब

बदलाव और समर्थन का सीधा संकेत : सुशील शर्मा

जालंधर। भारतीय जनता पार्टी शहरी जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा ने जालंधर कैंट हलके में संपन्न हुई जी राम जी योजना चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैंट हलका वासियो का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में उमड़ा जनसैलाब बदलाव और समर्थन का सीधा संकेत दे रहा है।उन्होंने कहा कि मान सरकार की दमनकारी नीतियों की बदौलत जी राम जी योजना से वंचित लाभार्थियों का इतनी बड़ी मात्रा में पहुंचना बता रहा है कि लोग मोदी सरकार की योजना को पसंद करते है। उन्होंने कहा कि अब कैंट हलके में बेरोजगारी पूरी तरह खत्म होगी और काम न मिलने पर मोदी सरकार मनरेगा योजना में बेरोजगारी भत्ता भी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी द्वारा नए कानून का विरोध इसलिए कर रहे है वास्तव में इन लोगों को गरीब से ही नफरत है। वे नहीं चाहते कि गरीब को उनका हक मिले और उनके नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना मजदूरों के हितों को सुनिश्चित करते हुए गांवों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।कैंट विधानसभा के प्रभारी जिला भाजपा महामंत्री अशोक सरीन हिक्की ने सफल कार्यक्रम को लेकर फोल्डीवल, जमशेर, जंडियाला, कुक्कड़ पिंड, बांबियावाल, समराय, भोड़े सपराय, चित्त्यानी, लखनपाल, कंगनीवाल, धीना, सोफी पिंड,बरसाल,प्रताप पूरा, मीरापुर, खुनखुन, दादूवाल,नथेवाल,सूनर खुर्द,सरहाली समेत अलग–अलग गांवो से आये सभी लोगो का धन्यवाद ।जिन्होंने चौपाल सभा को रैली का रूप दिया ।सरीन ने कहा फोल्डीवल का यह कार्यक्रम साफ संदेश है की 2027 मे कैंट विधानसभा से भाजपा का विधायक बनेगा ।क्युकी पिछले लंबे समय से अकाली दल से विधायक बनकर कांग्रेस मे गये मौजूदा विधायक ने ग्रामीण इलाको के लोगो को सुविधा और सुरक्षा देने का कोई काम नहीं किया और कैंट विधानसभा मे कांग्रस और आप पार्टी के नेताओ की मिलीभगत के चलते नशा तस्करी,गुंडागर्दी,बेरोजगारी चरम सीमा पर है।

विकसित भारत' का गुमशुदा आधा हिस्सा: भारत की विकास संबंधी रणनीति के रूप में श्रम संहिताओं का महत्व

वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना अनिवार्य है। फिलहाल श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 41.7 प्रतिशत है और विकसित भारत का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक ले जाना है। लगभग 30–अंकों के इस अंतराल को पाटने का मूल मकसद राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भारत की विकास गाथा को सिर्फ आधे लोग ही नहीं, बल्कि सभी लोग आकार दें। शिक्षा, डिजिटल सुलभता और उद्यमिता के मामले में हुई प्रगति के बावजूद, अभी भी बहुत सी संभावनाओं का दोहन बाकी है। भारत को एक ऐसा श्रम इकोसिस्टम तैयार करना होगा जो महिलाओं को प्रवेश करने, टिके रहने तथा आगे बढ़ने में समर्थ बनाए और भारत के एकीकृत श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और समावेशन को उत्पादकता में बदलने का एक दुर्लभ मौका देता है।

जरा गौर करें – ई–श्रम पर पंजीकृत सीता नाम की उज़र प्रदेश की एक श्रमिक बच्चों की देखभाल की कोई सुविधा उपलज्ध नहीं होने के चलते अपने दो बच्चों का पालन–पोषण करते हुए, घर बैठकर एक ठेकेदार के लिए कपड़े सिलती है।

इससे उसे एक अनियमित आय होती है। उनके जैसी महिलाओं के लिए, नई श्रम संहिताएं एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकती हैं। पास की एक कपड़ा फैज़्ट्री अब औपचारिक अनुबंधों के साथ अलग–अलग पालियों में काम करने के लिए महिलाओं की भर्ती कर रही है। पहली बार, भारत के श्रम कानूनों का ढांचा सीता जैसी लाखों महिलाओं के लिए बाधक होने के बजाय उनका संबल बनने के लिए तैयार है।

वर्ष 2019 और 2020 के बीच अधिनियमित श्रम संहिताएं 29 बिखरे कानूनों को चार सुव्यवस्थित ढांचों – मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, पेशेगत सुरक्षा और औद्योगिक संबंध संहिताओं – में समेकित करती हैं। यह विधायी मंशा साहसिक है और अब अनेक राज्य तेजी से इन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास इस मंशा को प्रभाव में बदलने का एक महत्वपूर्ण मौका है और यह प्रभाव कुछ इस किस्म का है।

सामाजिक सुरक्षा: पहले कदम के रूप में दृश्यता

सामाजिक सुरक्षा संहिता मातृत्व, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बच्चों की देखभाल से जुड़े पहलुओं को शामिल करते हुए गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करती है। ई–श्रम पोर्टल पर 30.6 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 53 प्रतिशत यानी 16 करोड़ महिलाएं हैं। इस पोर्टल और आधार आधारित यूएएन के बीच का जुड़ाव (लिंकेज) इन हकों को किसी भी स्थान पर और किसी भी क्षेत्र (सेज्टर) में दिलाया जाना संभव बनाता है। यह बुनियादी ढांचा बच्चे के जन्म या देखभाल जैसे जीवन के प्रमुख बदलवों के दौरान होने वाली क्षति को कम कर सकता है।

दृश्यता तो महज पहला कदम भर है। पंजीकरण को कल्याणकारी वितरण प्रणालियों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के पास सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं हो, बल्कि उन्हें वास्तविक सहायता भी मिले। इससे महिलाओं को उनके रोजगार चक्र में सुरक्षित व टिकाए रखने के तौर–तरीकों को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकेगा। आर्थिक अवसंरचना के रूप में देखभाल

किसी भी महिला से अगर नौकरी छोड़ने की वजहों के बारे में पूछिए, तो अज़्सर एक ही जवाब मिलेगा – बच्चों की देखभाल। पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाज की स्थिति से संबंधित संहिता इसी समस्या से निपटती है। यह देश के लगभग 62 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समूहों को संयुक्त रूप से क्रेच स्थापित करने, देखभाल की लागत को वितरित करने और इसे अनुपालन संबंधी बोझ से हटकर एक सक्षमकारी आर्थिक अवसंरचना में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है। राज्यों को अब उद्योग संघों के साथ मिलकर इन क्रेचों को बड़े पैमाने पर संचालित करना होगा। विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों और एसईजेड में, ताकि किसी भी मां को नौकरी और अपने बच्चे की देखभाल के बीच चुनना न पड़े।

चौबीसों घंटे चलने वाली अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलना

ओएसएच संहिता की धारा 43 महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति देती है। इसमें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की रात की पाली और यहां तक ? ?कि खदानों में काम करना भी शामिल है, बशर्ते उनकी सहमति हो और पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। आर्थिक तर्क स्पष्ट है। महिलाओं को चौबीसों घंटे संचालित होने वाले विकास के क्षेत्रों में भाग लेने में समर्थ बनाना, समावेशिता और प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से लाभदायक स्थिति पैदा करता है। जैसे–जैसे सर्वोज़म कार्यप्रणालियां उभर कर सामने आयेंगी और राज्यों के बीच साझा की जायेंगी, इन सक्षमकारी प्रावधानों को व्यापक रूप से अपनए जाने और उनमें सुधार किए जाने की उज्मीदें भी बढ़ेंगी। मेज पर एक जगह; महिलाओं की आवाज को संस्थागत बनाना

मजदूरी संहिता जोकि सर्वाधिक विचारपूर्ण सुधारों में से एक है – सभी केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों में एक तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य करती है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 16 फ़रवरी 2026

एमसीएल हीराकुद इंटरनेशनल हाफ मैराथन में १० हजार से ज्यादा एथलीटों ने लिया हिस्सा

संबलपुर १५/०२ (संवाददाता): महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने संबलपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर एमसीएल हीराकुड इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक इवेंट ओडिशा के संबलपुर में मशहूर हीराकुव डैम पर हुआ, जिसमें कुल 55 लाख रुपये की इनामी राशि थी, जिसमें दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा उत्साही प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रोफेशनल मैराथन ध ावक, फिटनेस के शौकीन, युवा और बूढ़े शामिल थे। देश के लगभग 20 राज्यों और केन्या, नाइजीरिया, भूटान, नेपाल और अन्य देशों के इंटरनेशनल एथलीटों ने इस ऐतिहासिक मैराथन में हिस्सा लिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, राजस्व मंत्री, ओडिशा सरकार श्री सुरेश पुजारी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पेयजल मंत्री श्री रबी नारायण नाइक, श्री सूर्यबंशी सूरज, खेल और युवा सेवा मंत्री, ओडिशा सरकार सांसद व विधाक ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई।इस मौके पर कोल इंडिया लिमिटेड के जाने–माने लोग, एमसीएल के सीएमडी श्री उदय अनंत काओले, एमसीएल के फंक्शनल डायरेक्टर्स, आईजी–नॉर्दर्न रीजन ओडिशा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संबलपुर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, संबलपुर, ओडिशा के अलग–अलग जिलों के सीनियर ऑफिसर्स और पद्मश्री अवार्डी श्रीमती कृष्णा पटेल और श्री जितेंद्र हरिपाल मौजूद थे।

21াउ हाफ मैराथन, 10াउ रन और 5াउ रन वाली रेस में पार्टिसिपेंट्स ने स्पोर्ट्समैनशिप, एंड्योरेंस और डिटरमिनेशन दिखाया, जिससे यह एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स और न्यूकमर्स, दोनों के लिए कॉम्पिटिटिव और मजेदार बन गया, जिससे हीराकुड का सुंदर नजारा हेल्थ, फिटनेस और एथलेटिक एक्सीलेंस के एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन में बदल गया।

मिस सोनिका और पंचानन बेरा ओवरऑल विनर रहे और उन्होंने फीमेल और मेल कैटेगरी में हाफ मैराथन का टॉप प्राइज क्रमशः 5 लाख जीता। नाइजीरिया के इंटरनेशनल एथलीट न्गांगा जॉर्ज और सरोन मोल्ला यिगजॉ ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अपनी–अपनी कैटेगरी में टॉप पांच फिनिशर में जगह बनाई। जाने–माने लोगों ने अलग–अलग कैटेगरी के विजेताओं को इनाम दिए।

देश को एनर्जी सिक्योरिटी देने में कोल इंडिया और डब्स के योगदान का जश्न मनाने के अलावा, इस इवेंट में हीराकुड को एक वर्ल्ड–क्लास टूरिस्ट हब के तौर पर भी दिखाया गया।

ओडिशा के सीएम ने मृतक ऑटोरिज़्शा ड्राइवर के लिए 4 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की

भुवनेश्वर १५/०२ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के रूपाली स्क्वायर में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक ऑटोरिज़्शा ड्राइवर के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सीएम ने दुख जताया, CMRF से आर्थिक मदद की घोषणा की मुज़्यमंत्री ने जाजपुर जिले के एक ऑटोरिज़्शा ड्राइवर विष्णु पात्रा की दुखद मौत पर गहरा दुख जताया और दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ष्टरूह्र ओडिशा ने आज ङ्क हैंडल पर पोस्ट किया कि यह अनुग्रह राशि मुज़्यमंत्री राहत कोष से मृतक के करीबी रिश्तेदारों को दी जाएगी।

हादसा कैसे हुआ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जानलेवा हादसा तब हुआ जब रूट नंबर 32 पर चल रही एक तेज़ रफ़्तार अमा बस ने व्यस्त रूपाली स्क्वायर जंक्शन पर पीछे से ऑटोरिज़्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटोरिज़्शा आगे चल रही एक दूसरी बस से टकरा गया, जिससे वह दोनों गाड़ियों के बीच में आ गया और उसे बहुत नुकसान हुआ। लोगों के विरोध से ट्रैफिक रुका इस घटना के बाद, लोकल लोगों और आने–जाने वालों ने विरोध में रोड जाम कर दिया, और जवाबदेही तय करने और बेहतर रोड सेफ़्टी उपायों की मांग की।

विरोध के कारण वाणी विहार–शाहिद नगर रोड पर कई घंटों तक भारी ट्रैफिक जाम रहा। रोड सेफ़्टी उपायों की मांग इस घटना ने एक बार फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहर की बिज़ी सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन की सेफ़्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और आने–जाने वालों ने अधिकारियों से भविष्य में ऐसे एज़्सीडेंट रोकने के लिए और सज़्त कदम उठाने की अपील की है।

सीएम ने दुख जताया, CMRF से आर्थिक मदद की घोषणा की मुज़्यमंत्री ने जाजपुर जिले के एक ऑटोरिज़्शा ड्राइवर विष्णु पात्रा की दुखद मौत पर गहरा दुख जताया और दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

राजनगर बीडीओ पर हमले की कोशिश के खिलाफ बीजद ने किया विरोध प्रदर्शन

केंद्रपाड़ा १५/०२ (संवाददाता): जिले के राजनगर इलाके में तनाव फैल गया, जब ज़्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ कथित तौर पर गाली–गलौज की गई और कुछ ब्ख्क्क कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की, ज़्योंकि उन्होंने शुक्रवार को कुछ पेंडिंग बिल पास करने से मना कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि राजनगर की ब्ख्ठ्ठ तिलोज़मा प्रुस्ती अपने ऑफिस चैंबर में थीं, तभी उनके नेता ललित कुमार बेहरा के नेतृत्व में करीब 30 ब्ख्क्क कार्यकर्ता कथित तौर पर अंदर घुस आए और उन पर कुछ बिल पास करने और एज़्स्ट्रा काम की मंजूरी देने का दबाव डाला। हालांकि, जब उन्होंने मना किया, तो कथित तौर पर उन्होंने उनके साथ गाली–गलौज की और उन पर हमला करने की भी कोशिश की। ष्टष्टञ्जङ्क फुटेज के मुताबिक, बेहरा ने कथित तौर पर प्रुस्ती पर लैपटॉप फेंकने की कोशिश की, लेकिन ऑफिस में मौजूद दूसरे स्टाफ ने उन्हें समय रहते रोक लिया। इस घटना का विरोध करते हुए, शनिवार को कई ब्ख्द्ब कार्यकर्ताओं ने मुज़्य सड़क पर करीब चार घंटे तक जाम लगाया और पंचायत समिति ऑफिस के सामने धरने पर भी बैठे, जिसमें शामिल लोगों के खिलाफ सज़्त कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना की निंदा करते हुए, ब्ख्द्ब के सीनियर लीडर और राजनगर के स्नुध्रुबा साहू ने आरोप लगाया कि जब से ब्ख्क्क सरकार सज़ा में आई है, जिले में क्रिमिनल एज़्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। उन्होंने दावा किया, रूलिंग ब्ख्क्क गलत लोगों को सपोर्ट कर रही है और पुलिस पर उनके खिलाफ कोई एज़्शन न लेने का दबाव डाल रही है। इलाके में क्राइम रेट अचानक बढ़ जाने से लोग पैनिक में हैं और हमेशा डर में जी रहे हैं।जब ब्ख्क्क लीडर बेहेरा से कॉन्टैज़्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि ब्ख्ठ्ठ की ड्यूटी है कि वह 20 लाख से कम के किसी भी डेवलपमेंट वर्क को ज़्लॉक चेयरपर्सन की मंजूरी के बिना मंजूरी दे। उन्होंने कहा, लेकिन ब्ख्ठ्ठ हर तरह के काम के लिए ज़्लॉक चेयरपर्सन की मंजूरी का इंतज़ार करती हैं, जिसकी वजह से कई प्रोजेज़्ट्स कछुए की रफ़्तार से चल रहे हैं। इसलिए, हम शुक्रवार को उनके ऑफिस गए थे, उनसे उन कामों को तेज़ी से पूरा करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से, मैंने गुस्से में बस लैपटॉप उठा लिया, लेकिन उन पर हमला नहीं किया। हालांकि, ब्ख्ठ्ठ तिलोज़मा प्रुस्ती और केंद्रपाड़ा कलेज़्टर रघुराम आर अय्यर ने इस घटना पर कमेंट करने से मना कर दिया।

35 नवोदय विद्यालय के छात्र पीलिया से प्रभावित

खोरधा १५/०२ (संवाददाता):ओडिशा के खोरधा जिले के गुरुजंग जवाहर नवोदय विद्यालय के कम से कम 35 छात्र पीलिया से प्रभावित हुए हैं, जिससे माता–पिता और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है।स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रभावित छात्र कक्षा ङ्कढ्ढ से ङ्गढ्ढढ्ढ तक के हैं। सूत्रों ने बताया कि छात्र 20 दिसंबर से इस बीमारी से पीड़ित हैं। मामले सामने आने के बाद, स्कूल अधिकारियों ने छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया।एहतियात के तौर पर, पीलिया से पीड़ित कई छात्रों को उनके घरों पर भेज दिया गया है, जबकि अन्य मेडिकल देखरेख में स्कूल परिसर में ही हैं। हालांकि बीमारी फैलने का सटीक कारण अभी तक पता

नहीं चला है, लेकिन कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल परिसर में दूषित पीने के पानी के कारण यह बीमारी फैली होगी। हालांकि, संक्रमण के स्रोत के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है। स्थिति के जवाब में, स्कूल अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर उनसे स्कूल परिसर में एक मेडिकल कैंप आयोजित करने का आग्रह किया है ताकि छात्रों को इलाज प्रदान किया जा सके और आवश्यक स्वास्थ्य जांच की जा सके।

स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एनसी चक्र ने कहा, पीलिया से प्रभावित एक छात्र छुट्टी के बाद स्कूल लौटा था, लेकिन उसने अधिकारियों को अपनी बीमारी के बारे में सूचित नहीं किया। स्थिति का पता चलने के बाद, उसे तुरंत मेडिकल इलाज दिया गया। एहतियात के तौर पर, स्कूल परिसर में सभी पानी की टंकियों को अच्छी तरह से साफ किया गया। छात्रों को भी बीमारी के बारे में जागरूक किया गया, और उन्हें सलाह देने के लिए स्वास्थ्य टीमों को बुलाया गया। भोजन और पीने के पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया और वे सुरक्षित पाए गए। यह एक वायरल संक्रमण था जो छुट्टी के बाद स्कूल आए प्रभावित छात्र से फैला था।फ्

स्टाफ नर्स शांतिलता ने कहा, जब भी यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, प्रभावित छात्रों को तुरंत मेडिकल इलाज दिया गया और घर भेज दिया गया। पीलिया से पीड़ित एक छात्र ने स्कूल अधिकारियों को अपनी बीमारी के बारे में सूचित नहीं किया था, और माना जाता है कि जब वह इनज़्यूबेशन पीरियड में था, तब यह बीमारी फैली। उस समय, पांच से छह छात्र प्रभावित हुए थे, और अगले महीने से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच, कुछ छात्र कड़ाके की ठंड के कारण सर्दी और खांसी से पीड़ित हैं, जिससे कुछ अभिभावक पीलिया के संदेह में अपने बच्चों को घर ले गए हैं। एहतियात के तौर पर, स्कूल अधिकारियों ने आज 20 छात्रों को अस्पताल ले जाया है, और उनकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है।

बीजेपी नेता पीतांबर पांडा हत्याकांड, चार्जशीट दाखिल की जाएगी

राउरकेला १५/०२ (संवाददाता): बीजेपी नेता और सीनियर वकील पीतांबर पांडा हत्याकांड में एक बड़े अपडेट में, पुलिस आज छुट्टी होने के बावजूद रविवार को चार्जशीट दाखिल करने वाली है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट आज कोर्ट में पेश की जाएगी और यह 30,000 से ज़्यादा पन्नों की होगी, जो जांच के पैमाने और जटिलता को दिखाता है। पीतांबर पांडा की हत्या 6 अज़्टूबर, 2025 को हुई थी। अब तक, इस मामले में पूर्व ब्ख्द्ब विधायक बिक्रम पांडा सहित 16 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जांचकर्ताओं ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से जांच एक अहम पड़ाव पर पहुंच जाएगी, जिससे ट्रायल की कार्यवाही शुरू होने का रास्ता साफ होगा।

केंद्रपाड़ा में ज़मीन विवाद में हिंसा, 1 की मौत, 2 घायल

केंद्रपाड़ा १५/०२ (संवाददाता): सदर पुलिस स्टेशन के तहत नरिलो गांव में ज़मीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान उपेंद्र ओझा के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना ज़मीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के परिवार के अंदर शारीरिक हिंसा में बदलने के बाद हुई। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम को तनाव फिर से बढ़ गया जब राजकिशोर ओझा ने कथित तौर पर अपने भतीजे उपेंद्र से विवाद को लेकर बहस की। यह कहा–सुनी धीरे–धीरे बढ़ गई और आखिरकार हिंसक टकराव में बदल गई।

पारिवारिक विवाद के बाद हमला पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजकिशोर ओझा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर कथित तौर पर क

हथियारों का इस्तेमाल करके उपेंद्र पर हमला किया। हमले के दौरान, राजकिशोर ने कथित तौर पर उपेंद्र पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हमले में उपेंद्र के माता–पिता, संजुक्ता और सरोज कांता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, मेडिकल इलाज के बावजूद, उपेंद्र ने उसी रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीछे छूटा परिवार मृतक, उपेंद्र ओझा के परिवार में उनकी पत्नी और एक साल की बेटी है। घायल परिवार के दो सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और रिपोर्ट लिखे जाने तक उनका मेडिकल सुविधा में इलाज चल रहा था। पुलिस ने कहा कि चल रही जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरएसपी के सीएमएम एवं एमएसएस विभाग के कर्मचारी सेल शाबाश पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित

राउरकेला १५/०२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र में केंद्रीय अनुरक्षण (मैकेनिकल) (सीएमएम) एवं एमएसएस विभाग के 18 कर्मचारियों को मरम्मत भवन के सम्मलेन कक्ष में आयोजित एक समारोह में सेल शाबाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिकल), श्री डी के पालो ने समारोह की अध्यक्षता की तथा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएमएम),श्री एस के पंका, अनुभागों के प्रमुख, वरिष्ठ अधि ाकारी, मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि एवं सीएमएम के अंतर्गत आनेवाले विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधि वर्ग उपस्थित था।अपने संबोधन में श्री पालो ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बधाई दी,

उनके समर्पण एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा सभी से अनुरोध किया कि वे रखरखाव में उत्कृष्टता प्राप्त करने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु उसी जोश और अटूट प्रतिबद्धता के साथ अग्रणी भूमिका निभाएँ।श्री पंका ने भी पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए उनके उत्कृष्ट समर्पण की प्रशंसा की तथा कार्यबल को उनके उत्साह, स्वामित्व की भावना एवं कड़ी मेहनत से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। इन कर्मचारियों को रखरखाव, गुणवत्ता, योजना एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक (सीएमएम), श्री डी सोरेन द्वारा किया गया।